विचार बिन्दु

कदम पीछे ना हटाने वाला ही ऐश्वर्य को जीतता है। –ऋग्वेद

जीवनशैली को बदल रही आर्थिक नीतियां और प्रौद्योगिकी

खुली आर्थिक नीतियों के बाद दो दशकों में भारत की सामाजिक संरचना में भले ही ज्यादा बदलाव नहीं हुआ हो, किन्तु डिजिटल तथा अन्य तकनीकी विकास के कारण यहां के लोगों की आदतों और रीति-रिवाजों में व्यापक परिवर्तन जरूर नज़र आता है। यह परिवर्तन केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, आपसी संबंध, काम करने के तरीकों और उपभोग की संस्कृति तक फैले हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स ने भारतीय उपभोक्ता को रात और दिन चौबीसों घंटे बाजार से जोड़ दिया है। अब खरीदारी केवल जरूरत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इच्छा-आधारित उपभोग का रूप ले चुकी है। ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लैश सेल और डिजिटल भुगतान ने खर्च को सहज बनाया है।अभी खरीदो, बाद में चुकाओ जैसी सुविधाओं ने ऋण-आधारित जीवनशैली को बढ़ावा दिया है। डिजिटल तकनीक रोजगार और कार्य-संस्कृति को भी नया रूप दे रही है। वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग और गिग इकॉनॉमी समय और स्थान की बाधा तोड़ रही है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स ने संवाद को तेज़ और व्यापक बना दिया है, पर ऐसा भी माना जाता है कि उसकी गहराई कम कर दी है। यह भी लग रहा है कि परिवार और पड़ोस के आपसी प्रत्यक्ष संवाद में कमी आ रही है। स्टार्ट-अप संस्कृति और ऐप-आधारित सेवाओं ने युवाओं में उद्यमिता की सोच को बढ़ावा दिया है। नौकरी की स्थिरता घटी है और कार्य तथा निजी जीवन की सीमाएं धुंधली होने लगी हैं। तकनीक ने जीवन को तेज़, प्रतिस्पर्धी और परिणाम-केंद्रित बना दिया है। धैर्य, प्रतीक्षा और संतोष जैसी प्रवृत्तियां कमजोर हुई हैं। सब कुछ तुरंत चाहिए वाली मानसिकता विकसित हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समय और जीवन के संतुलन पर पड़ रहा है। लोगों की जीवनशैली तो स्पष्ट रूप से बदल रही है। छोटी जगहों के युवा अच्छे पैकेज पर अपनी जगह छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। ऊंची-ऊंची फ्लैटों वाली बिल्डिंगें हमारे शहरों की पहचान बदल रही हैं। आधिकारिक तौर पर सबसे अधिक शुद्धतावादी माने वाले भारतीय समाजमें यौन अनुमति देने वाली पीढ़ी विस्तार पा रही है। शहरी जीवन का नया बहुराष्ट्रीय और बहुजातीय चरित्रबन रहा है। नये समय में एक तरफ जहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ गांवों में अब भी झोपड़ियों में जीवन बिताते लोग भी मिलते है और शहरों में कच्ची बस्तियों का जाल हर कहीं नज़र आता है। खुली अर्थनीतियों और नये नैतिक प्रतिमानों में लोग राजशाही के नॉस्टैल्जिया, वंशानुगत वंशावली, शासकीय सम्मान और आडंबरपूर्ण रीति-रिवाजों और समारोहों के बोझ से दबे हुए नज़र आते हैं। देश में संवैधानिक-गणतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद अनेक मौकों पर यहां की शासन व्यवस्था राजसी ठसक वाली और वैसी ही अन्यायपूर्ण भी देखने को मिलती है।

भारत मिथकों से प्यार करने वाला देश रहा है। इसी कारण यहां की सामाजिक स्थिति का यथार्थवादी मूल्यांकन करना हमेशा ही कठिन रहा है। अंग्रेजों के जाने के बाद हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया मगर ब्रिटेन के 1935 के कानून की मूलभूत संरचनाओं में वास्तविक और बड़ा जमीनी परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। समग्र रूप से देखें तो पाते हैं कि इस कारण देश में आजादी के बाद वर्ग संरचना या व्यवसायों के वितरण तथा प्रशासन में कोई क्रांतिकारी या नाटकीय परिवर्तन नहीं हो पाया है। भले ही कृषि की जीडीपी में भूमिका कम होकर करीब 14 प्रतिशत रह गई है, मगर उस पर अब भी 45 प्रतिशत आबादी आश्रित है। राज्य अब भी प्रमुखता वाला और लोकप्रिय नियोक्ता बना हुआ है। अधिकतर श्रमिक अकुशल हैं, और वे रोज गांवों से चल कर नजदीकी शहरों में मजदूरी के लिए आते हैं। अतीत के श्रमिक वर्ग समुदाय, एकजुटता वाले संगठन अपना जुझारू चरित्र खो चुके हैं। भारत में वर्ग मतभेद न केवल मजबूत बने हुए हैं बल्कि अब तो वे अहंकारों में बदल गए हैं। साधन संपन्न लोगों के सभी चुनिंदा निजी शिक्षण संस्थान व्यावसायिक हो गये हैं जिनकी फ़ीसें चौकने वाली हैं। ऐसी पब्लिक स्कूलें अप्रतिम समृद्धि अर्जित करती हैं। शिक्षा आगे बढ़ने की सीढ़ी बनने के बजाय एक ऐसी छलांग बन गई है, जो गरीब नहीं लगा पाता। यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है जो अब पूरी तरह कॉर्पोरेट जगत के अधीन हो चुकी हैं और जिनके मकड़जाल में चिकित्सक भी फंस रहे हैं। बीमार शरीर और कर्ज़ में डूबा परिवार आर्थिक पायदान पर ऊपर कैसे चढ़े? सरकार का आधिकारिक चेहरा पूरी तरह पूंजी के ताप में दमक रहा है। सत्ता भी जीडीपी के आंकड़ों की धुंध में असमानता की खाई को ढके रखना चाहती है। आज भी संविधान के प्रावधान के बावजूद सब बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल रही है। गरीबों और अमीरों के स्कूल का भेद बना हुआ है क्योंकि शिक्षा के अधिकार कानून का मोल उस कागज की रद्दी से अधिक नहीं है जिस पर वह छपा है। असमानता वाली शिक्षा व्यवस्था ने अधिकांश बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा से पूरी बाहर कर रखा है। उनमें शुरू से ही यह भावना भर दी जाती है कि वे स्थायी रूप से हीन हैं। यह तथ्य कि शिक्षा सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए खुली है, केवल उनके बाहरी होने की भावना को रेखांकित करती है। अमीर इतने अमीर हैं कि वे सामाजिक बहुमत से अलग हो जाते हैं। खुली आर्थिक नीतियों ने अमीरों को अपने धन के प्रदर्शित का साहस और स्वाद दिया है। उनकी कार्यप्रणाली उन्हें उन लोगों से अलग करती है जो वेतन पर जीवन यापन करते हैं। वेतनभोगी अपनी आय पर कर का भुगतान करते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह सीधे उनके वेतन से काटा जाता है। लेकिन जो लोग संपत्ति या वाणिज्यिक उद्यमों से आय का आनंद लेते हैं, उनके पास कर से बचने के अनेक उपाय और उपकरण है, जिससे उनकी कानूनी पिरामिड में ऊपर तक पहुंच बनी हुई है। सामाजिक पैमाने के निचले स्तर पर, अकुशल या अर्ध-कुशल शारीरिक मजदूरों वाली आबादी का एक तिहाई हिस्सा अनिश्चित भविष्य के साथ श्रमसाध्य दिनचर्या का सामना करता है। असंगठित क्षेत्र में आय से केवल जीविका चलती है, प्रगति नहीं होती।

तकनीक ने जीवन को तेज़, प्रतिस्पर्धी और परिणाम-केंद्रित बना दिया है। धैर्य, प्रतीक्षा और संतोष जैसी प्रवृत्तियां कमजोर हुई हैं। सब कुछ तुरंत चाहिए वाली मानसिकता विकसित हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समय और जीवन के संतुलन पर पड़ रहा है। लोगों की जीवनशैली तो स्पष्ट रूप से बदल रही है। छोटी जगहों के युवा अच्छे पैकेज पर अपनी जगह छोड़ कर बाहर जा रहे हैं।

पारंपरिक राजनीति के प्रति अब किसी का रुझान नहीं है। प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति प्रचलन में है, जिसमें जन प्रतिनिधि स्थानीय लोग नहीं तय करते है, बल्कि पार्टी संगठनों के आलाकमान उन्हें चुनते हैं। हालांकि यह कभी कोई नहीं जान पाता कि पार्टी आलाकमान क्या और कौन है? यह ढांचा सभी पार्टियों में रहस्य बना रहता है। पूंजी और श्रम के संगठनात्मक ढांचे रूढ़िवादी और अक्षम है। यही कारण है कि देश में मेन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में विकास की दर सबसे कम बनी हुई है। देश में ध्रुवीकृत सामाजिक संरचना बनाने की तेज होती कोशिशें बेचैन करती हैं। हालांकि कोई भी भारत में सामाजिक क्रांति की उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन, कोई भी तेजी से भारतीयकरण की उम्मीद भी नहीं कर रहा है, सिवाय उन सतही मामलों के जो किसी भी आधुनिक औद्योगिक समाज को पसंद आते हैं, विशेष रूप से उपभोक्ता सामान। भारत की राजनीतिक संभावनाएं ऐसी ही है। जिस विकास के दावे आज किए जा रहे हैं, बहुसंख्यक जन उस विकास के मात्र दर्शक बने हुए हैं, भागीदार नहीं। आज भी जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्र अधिकतर मामलों में अवसर तय होते हैं। नेटवर्किंग और सिफ़ारिश जिनके पास होती है वे अवसर पा जाते हैं और असमर्थ, जो केवल अपनी योग्यता पर निर्भर करता है, वह अपने को धकेला हुआ पाता है, क्योंकि बराबरी की दौड़ में कुछ लोग 100 मीटर आगे से दौड़ शुरू करते हैं। सरकारी योजनाएं जो लाभार्थी को सीधे नकद या अन्न देती है वह बस भूख को कम करती हैं, तात्कालिक राहत प्रदान करती हैं। लेकिन ये योजनाएं गरीब को आत्मनिर्भर उद्यमी या कुशल कारीगर या कर्मचारी नहीं बनातीं। गरीबी प्रबंधित हो रही है, समाप्त नहीं। शहरीकरण और पलायन का जाल पीढ़ीगत गरीबी का निर्माण कर रहा है। गरीब इसलिए पीछे नहीं है कि वह मेहनती नहीं है, बल्कि इसलिए हैं कि शासन व्यवस्था मेहनत को अवसर में बदलने का उपाय करने में असफल हो रही है। शासन आज के भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा देने का दावा कर रहा है। जीडीपी के आंकड़े उत्साह से भरे हैं, शेयर बाज़ार नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन इस चमक के नीचे एक कड़वी सच्चाई छिपी है – भारत का गरीब उसी तेजी से आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ पाने में अपने को असमर्थ पा रहा है। कुछ हाथों में सीमित पूंजी के बढ़ने से देश की जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखती है किन्तु दूसरी तरफ प्रतिव्यक्ति जीडीपी हमें दूसरी सच्चाई से भी रूबरू कराती है। सवाल यह नहीं कि विकास क्यों नहीं हो रहा, सवाल यह है कि विकास सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल पा रहा? हमें यह तय करना है कि हम केवल आर्थिक वृद्धि चाहते हैं या समान अवसरों पर आधारित प्रगति, क्योंकि बिना सामाजिक गतिशीलता के कोई भी विकास न टिकाऊ होता है, न न्यायपूर्ण। विकास का मतलब है गरीब का गरीब न रहना, अगली पीढ़ी का बेहतर जीवन जी पाना, और मेहनत के दम पर सामाजिक-आर्थिक हैसियत बदल सकना। यह प्रक्रिया जब ठहर जाती है, तो समाज में असंतोष, हताशा और असमानता गहराने लगती है। देश आज इसी मोड़ पर खड़ा है। जहां सुविधाएं बढ़ी है, वहीं अति उपभोग और वित्तीय असंतुलन की आशंका भी बढ़ी है, जो सामाजिक अलगाव, मानसिक दबाव और होड की जीवनशैली को जन्म ले रही है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा,
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राजस्थान के बजट के 75 साल का बहीखाता

डॉ. कैलाश चन्द सैनी

राजस्थान का वर्ष 1952 से 2026 तक का बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज़ नहीं रहा, बल्कि सत्ता, संसदीय परम्परा और परिपक्वता की कहानी भी कहता है। यह 75 वर्षों की उस वित्तीय यात्रा का बहीखाता है, जिसने मरु प्रदेश के विकास की दिशा तय की है।

किसी भी विधानसभा के दो प्रमुख काम होते हैं– विधायी और वित्तीय। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विधानसभा ने पिछले 75 वर्षों में न केवल राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी कानूनों का निर्माण किया है, बल्कि प्रतिवर्ष राज्य का बजट पारित कर प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा भी निर्धारित की है। वर्ष 1952 से अब तक की इस यात्रा में जहाँ एक ओर आंकड़ों की विस्तृत दुनिया दिखाई दी है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नेतृत्व के अनेक रोचक और अर्थपूर्ण रंग भी उभरकर सामने आए हैं। पचहत्तर वर्षों के इस संसदीय इतिहास में विधानसभा के सम्मानित सदन में वित्त मंत्रियों द्वारा 74 बार बजट भाषण प्रस्तुत किया जाना इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान ने अपने विकास के हर उतार-चढ़ाव को सजगता और गंभीरता से देखा-परखा है।

शुरुआती सारथी : मिर्धा से व्यास तक

राजस्थान के वित्तीय इतिहास का श्रीगणेश 7 अप्रैल 1952 को हुआ, जब नाथूराम मिर्धा ने पहले वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1952-53 का बजट प्रस्तुत किया। राजस्थान की राजनीति के इस कद्दावर नेता का व्यक्तित्व आगे चलकर इतना प्रभावी सिद्ध हुआ कि वे 1979-80 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रहे। अब तक राजस्थान के वित्तीय इतिहास में 20 वित्त मंत्रियों ने राज्य का बजट प्रस्तुत किया है। यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा यह भी रही है कि कई अवसरों पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने स्वयं वित्त विभाग का दायित्व संभालते हुए बजट प्रस्तुत किया। इसी परंपरा की शुरुआत करते हुए जयनारायण व्यास 17 मार्च 1953 को राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी स्वयं निभाई। इसके ठीक बाद, 12 मार्च 1954 को टीकाराम पालीवाल ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पालीवाल इससे पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री – दोनों पदों पर रह चुके थे।

सुखाड़िया युग : सत्रह वर्षों का 'शून्य बजट प्रस्तुति' काल

राजस्थान के वित्तीय इतिहास का सबसे रोचक और विश्लेषणात्मक तथ्य मोहनलाल सुखाड़िया से जुड़ा है। लगभग 17 वर्षों (1954-1971) तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने स्वयं कभी बजट प्रस्तुत नहीं किया। यह निर्णय सत्ता के विकेंद्रीकरण और मंत्रियों की वित्तीय विशेषज्ञता पर उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है। उनके कार्यकाल में बृजसुन्दर शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, बालकृष्ण कौल और मथुरादास माथुर जैसे दिग्गज वित्त मंत्रियों ने सदन में राज्य के आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत किए।

इनमें हरिभाऊ उपाध्याय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1952-56 तक अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद 1957-62 के दौरान राजस्थान का पाँच बार बजट प्रस्तुत किया। यह दौर इस बात का उदाहरण है कि राजस्थान की वित्तीय परंपरा व्यक्ति-केंद्रित न होकर संस्था-केंद्रित रही।

आंकड़ों के जादूगर : गहलोत और राजे

आधुनिक राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का नाम वित्तीय प्रबंधन और बजट प्रस्तुति के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुखाड़िया के बाद सबसे लंबे समय तक राज्य की बागडोर संभालने वाले अशोक गहलोत 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। प्रारंभ में उन्होंने अपने पास किसी भी विभाग का प्रभार नहीं रखा और बजट की जिम्मेदारी विश्वस्त वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को सौंपी, जिन्होंने चार बार बजट प्रस्तुत किया। प्रद्युम्न सिंह ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्हें विधानसभा के टाउन हॉल स्थित पुराने भवन और ज्योतिनगर स्थित नए भवन- दोनों में बजट पेश करने का अवसर मिला। तेरहवीं और पंद्रहवीं विधानसभा के कार्यकाल में अशोक गहलोत ने अपने सभी 10 बजट स्वयं प्रस्तुत किए।

इसी प्रकार, वसुंधरा राजे ने बारहवीं और चौदहवीं विधानसभा के अपने दोनों कार्यकालों में सभी 10 बजट स्वयं पेश कर सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसकी बराबरी आगे चलकर अशोक गहलोत ने की। तीन बार प्रदेश की बागडोर संभालने वाले भैरोंसिंह शेखावत अपने दूसरे और तीसरे कार्यकाल में कुल 6 बार बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री रहे। उनके पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री मास्टर आदित्येन्द्र ने बजट पेश किया। शेखावत ने अंत्योदय जैसी योजना को लागू कर राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई।

जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर भी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक बार बजट प्रस्तुत करने का दायित्व निभाया। पहाड़िया लोकसभा और राज्यसभादोनों सदनों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और केंद्र सरकार में वित्त उपमंत्री भी रहे। पहली से दसवीं विधानसभा तक लगातार विधायक निर्वाचित होकर हरिदेव जोशी ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। वे जहाँ तीन बार मुख्यमंत्री रहे, वहीं शिवचरण माथुर भी दो बार प्रदेश की बागडोर संभाल चुके थे।

चन्दनमल बैद वित्तीय विशेषज्ञ

यदि केवल वित्त मंत्री के रूप में प्रभाव और निरंतरता की बात की जाए, तो चन्दनमल बैद का स्थान विशिष्ट है। उन्होंने बरकतुल्ला खां (दो बार), हरिदेव जोशी (चार बार), शिवचरण माथुर (एक बार) और अशोक गहलोत (एक बार) – कुल चार मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में आठ बार बजट प्रस्तुत किए। वे सही अर्थों में राजस्थान के सबसे अनुभवी और विशेषज्ञ वित्त मंत्रियों में गिने जाते हैं।

लोकसभा में प्रस्तुत हुआ राजस्थान का बजट

इतिहास सदैव एकरेखीय नहीं होता। एक अवसर ऐसा भी आया जब राष्ट्रपति शासन के कारण राजस्थान विधानसभा के स्थान पर राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति ने वर्ष 1993-94 का बजट लोकसभा में पेश किया। वित्तीय विषयों में सिद्धहस्त और अनुभवी मानिकचन्द सुराणा की यह विडंबना रही कि वित्त मंत्री होने के बावजूद सीमित कार्यकाल के कारण उन्हें सदन में बजट भाषण देने का अवसर ही नहीं मिल सका। इसी प्रकार, मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे हीरालाल देवपुरा भी वित्त विभाग का दायित्व होने के बावजूद बजट प्रस्तुत नहीं कर पाए।

बजट के तीसरे पड़ाव पर : दिया कुमारी

इतिहास के पन्नों से निकलकर वर्तमान की ओर दृष्टि डालें, तो उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज एक नई इबारत लिखने जा रही हैं। हरिशंकर भाभड़ा के बाद वे वित्त विभाग संभालने वाली प्रभावशाली उपमुख्यमंत्री हैं। 11 फरवरी 2026 को वे अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं, जो राजस्थान के विकसित होने के संकल्प की अगली कड़ी होगा। उल्लेखनीय है कि दो बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हरिशंकर भाभड़ा ने उपमुख्यमंत्री रहते हुए 1997-98 में दो बार बजट प्रस्तुत किया था।

निष्कर्ष– वर्ष 1952 के पहले बजट से लेकर 2026 के प्रस्तावित बजट तक राजस्थान ने आर्थिक विकास की एक लम्बी और सार्थक यात्रा तय की है। यह यात्रा केवल आय-व्यय के आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह उन नेतृत्वकर्ताओं की दूरदर्शी सोच को भी प्रतिबिंबत करती है, जिन्होंने मरू प्रदेश को एक विकसित और सशक्त राज्य बनाने का सपना देखा। विधानसभा के सदन में वित्त मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत 74 बजट भाषणों का यह लेखा-जोखा राजस्थान की राजनीतिक परिपक्वता, स्वस्थ संसदीय परंपराओं और आर्थिक विकास की जीवंत गाथा प्रस्तुत करता है।

- डॉ. कैलाश चन्द सैनी,
पूर्व मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधानसभा, जयपुर

पाली : जिला कारागृह के निरीक्षण में बंदियों से समस्यायें जानी

प्राधिकरण सचिव भाटी ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी ने जिला कारागृह, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया।

पाली, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी ने मंगलवार को जिला कारागृह, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान 78 बंदी जिला कारागृह, पाली में निरूद्ध मिले। इस दौरान सचिव भाटी द्वारा बंदियों से वार्तालाप कर कारागृह में भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त कोई भी बंदी निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हो अथवा विधिक सहायता के अभाव में बिना अधिवक्ता के कारागृह में निरूद्ध ना रहे, इसके लिए सचिव भाटी द्वारा कारागृह में बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। साथ ही ऐसे बंदी जिनकी जमानत होने के उपरांत भी कारागृह में निरूद्ध हो इस संबंध में भी जानकारी ली गई तथा बंदियों को उनके प्रकरणों की स्थिति के बारे में बताया। सचिव भाटी ने बंदियों से वार्तालाप कर समस्याओं के बारे में पूछा तथा नये बंदियों से वार्तालाप कर वक्त घटना/आरोपित अपराध के समय उनकी आयु के संबंध में जानकारी ली। सभी बंदी की ओपीडी के समय में स्वास्थ्य जांच की जाती है तथा इमरजेंसी होने पर बंदी को राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली रेफर किया जाता है। निरीक्षण के दौरान जोराराम कुमावत कारापाल जिला कारागृह पाली, रविंद्र परिहार मेलनर्स जेल डिस्पेंसरी पाली, अल्ताफ हुसैन सहायक जेल विजिटिंग लॉयर्स तथा इंटर्नशिप करने आए पुनित गोरा विधि विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से

■ **इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में 19 लाख 90 हजार 57 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं**

अजमेर, (निसं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार 12 फरवरी से राज्यभर में प्रारंभ होंगी। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में 19 लाख 90 हजार 57 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षाओं का आयोजन प्रदेशभर में 6194 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष सेकेंडरी परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 109, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 9 लाख 10 हजार 9, प्रवेशिका में 7 हजार 817 तथा वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4 हजार 122 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, उड़नदस्तों की तैनाती एवं विशेष दलों की नियुक्ति की गई है। इस साल जिलों में अभय कमांड सेन्टर से भी परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। बोर्ड सचिव ने परीक्षार्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने तथा बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने की अपील की है। परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन के लिए शिक्षक, केंद्राध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।

अज्ञात जंगली जानवर ने कई मवेशियों को मारा

सादुलपुर, (निसं)। गांव ग्वालीसर में सोमवार व मंगलवार की रात्रि को अज्ञात जंगली जानवरों के हमले में अनेक मवेशियों की मौत व घायल होने का मामला सामने आया है तथा अनेक मवेशी गायब बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पशुपालक नवीन अपने 85 मवेशियों को रिवाडे में बन्द कर पास ही बने मकान में सो गया। हमेशा की तरह सुबह 7-8 बजे मवेशियों को संभाला तो दंग रह गया। इसी दौरान रिवाडे में अनेक भेड़ लहूलुहान पड़ी थी, जिसमें कई मवेशियों की मौत हो चूकी थी तो कई मवेशी घायल थे। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग जल्द से जल्द अज्ञात जंगली जानवर का रेस्क्यू करें ताकि ग्रामीणजन व पशुपालकों को राहत मिल सके। पशुपालक नवीन ने बताया कि वह मवेशियों का पालकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर जीवन यापन करता है, मगर अब उसके सामने रोजी-रोटी का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि 35 मवेशी गायब हैं, तथा गांव में अज्ञात जानवर बताया जा रहा है।

उदयपुर : सामूहिक विवाह सम्मेलन में 40 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

उदयपुर, (का.सं.)। मंगलवार को राजपूत महासभा संस्थान, उदयपुर संभाग द्वारा आयोजित 27वें सामूहिक विवाह समारोह में 40 जोड़े शादी की सभी रस्में निभाने के बाद जीवनसाथी बने। 40 पण्डितों के एक साथ मंत्रोच्चार से फतह स्कूल का विशाल पाण्डाल गूंज उठा।

फतह स्कूल में विवाह की रस्में सम्पन्न होने से पूर्व टाउनहॉल से 40 घोड़ी एवं 10 बग्गियों में वर-वधू बैण्ड-बाजों की धुनों के साथ समाजजन नाचते-गाते टाउन हॉल से फतह स्कूल पहुंचे, जहां सभी दुल्हों ने तोरण की रस्म सम्पन्न की। बिंदौली में 40 घोड़ों एवं 10 सुसज्जित बग्घियों में सवार दूल्हा-दुल्हन उल्लास और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे।

दोपहर एक बजे विवाह स्थल पर तोरण रस्म विधिवत रूप से संपन्न हुई। जिसमें दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता सहित सैकड़ों समाजजन और रिश्तेदार उपस्थित रहे और उन्होंने नवयुगलों को अपना स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेघराज सिंह रॉयल ने समाज की एकता पर बल देते हुए कहा कि अब हमें संगठित होकर आगे बढ़ाना है। इसके पश्चात सभी वर-वधु पाण्डाल में पहुंच कर पण्डितों द्वारा किये गये मंत्रोच्चार एवं उनके बतायी गयी रस्मों को निभाते हुए परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में संस्थान के महासचिव प्रदीप सिंह भाटी, मेघराजसिंह रायल, पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, रामप्रताप सिंह डिग्गी, भाजपा नेता हिम्मतसिंह झाला, राजस्थान विद्यापीठ के वाइस चांसलर कर्नल प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत, भापजा नेता एवं पूर्व विधायक रणधीरसिंह भीण्डर, वीरेन्द्र रावणा, वीरमदेवसिंह कृष्णावत, यदुराजसिंह कृष्णावत को क्षत्रिय शिरोमणी विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 11 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र दिन 10:53 तक, व्याघात योग रात्रि 2:30 तक, गर करण प्रात: 9:59 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 10:53 तक है। भद्रा रात्रि 11:11 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:56 तक, शुभ 11:18 से 12:41 तक, चर 3:26 से 4:49 तक, लाभ 4:49 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 6:12

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।